

एमपी में अतिथि विद्वानों के मुद्दों पर बनेगी कमेटी

सीएम बोले-फिक्स सैलरी, नियमितीकरण समेत मांगों पर होगा विचार, अटकाने-लटकाने का समय गया

भोपाल। भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों की फिक्स सैलरी, नियमितीकरण और अन्य संबंधित मांगों पर विचार के लिए कमेटी बनाई जाएगी। देश के जिस भी राज्य का बेहतर मॉडल होगा, उसका अध्ययन कर मध्य प्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटकाने-लटकाने का समय गया, अब सरकार सकारात्मक सोच के साथ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से कहा कि वे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अतिथि विद्वानों की मांगों पर काम करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहयोग करेगी।



फिक्स सैलरी और नियमितीकरण पर होगा मंथन- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी अतिथि विद्वानों के लिए कई फैसले ले चुकी है। अब उनकी बाकी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा समेत जिस राज्य

में बेहतर व्यवस्था है, उसका अध्ययन कर मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि सरकार ने अतिथि विद्वानों को 13 आकस्मिक अवकाश, तीन ऐच्छिक अवकाश आदि घोषित कर रखे हैं।

मजदूर संघ ने उठाए सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने कहा कि अतिथि विद्वानों की सामाजिक सुरक्षा और अन्य संबंधित मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय शिक्षा परंपरा का उल्लेख करते हुए भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रसंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा दुनिया के लिए प्रेरणा रही है और नई शिक्षा नीति के जरिए मध्य प्रदेश देश में मिसाल बना है। अब किताबी ज्ञान के साथ नवाचार पर भी जोर दिया जा रहा है।

अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक

- 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी कफ सिरप और टॉनिक पर असर, ड्रग रूल्स 1945 में किया बड़ा बदलाव



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में यह बदलाव किया है। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को 'शेड्यूल एच 1' कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इनमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 12 फीसदी से ज्यादा होती है और जो 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती है।

मेडिकल स्टोर्स को 3 साल का रिकॉर्ड रखना होगा

मेडिकल स्टोर्स के लिए भी खास निर्देश हैं। अब मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड एक अलग रजिस्टर में रखना होगा। मार्केट में मिलने वाले कई कफ सिरप और टॉनिक में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। बिना रोक-टोक या डॉक्टर की पर्ची के मिलने से कई लोग इनका इस्तेमाल नशे के लिए करने लगे थे। इसी दुरुपयोग को रोकने और दवाओं की बिक्री की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स

हालांकि, जर्नल ऑफ मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसी दवाओं का बिना डॉक्टर की सलाह के या जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए, तो यह बच्चों, बुजुर्गों और लिवर के मरीजों के लिए गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। इस कदम से भारत में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम और मजबूत होगा। दवाओं की ट्रेसिबिलिटी बढ़ेगी यानी यह पता लगाना आसान होगा कि कौन सी दवा कहाँ और किसे बेची गई। इससे दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार

नरोत्तम ने नामांकन फॉर्म खरीदकर शुरू कर दी थी चुनावी सभाएं

भोपाल (नप्र)। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट



दिया है। माना जा रहा था कि यहां से बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देगी। नरोत्तम मिश्रा 2023 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेन्द्र भारती से अपना चुनाव हार गए थे। जबकि चर्चा पूर्व गुहमंजी नरोत्तम मिश्रा की हो रही थी। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। चुनावी जनसभाएं भी करनी शुरू कर दी थी। यह घोषणा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की सजा पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद की गई। आशुतोष तिवारी लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं। संभागीय संगठन मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश हाइसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।

नशा, नाश की जड़ है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को कर देता है बर्बाद

- सीएम बोले-2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में युवा शक्ति रचनात्मक भूमिका निभा रही है। सभी नागरिक भी विकासवात्मक गतिविधियों से स्वयं को जोड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति समाज की विकास यात्रा पर कुठाराघात करती है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। नशे से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने हर तरह के नशे पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की है। नशा, नाश की जड़ है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। नशे से सभी प्रकार की रचनात्मकता और आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कुठाराघात होता है, वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होते हैं। नशा परिवारों को बर्बाद कर देता है। राज्य सरकार ने अपनी समस्त क्षमताओं के साथ नशे के खिलाफ अभियान आरंभ किया है।

प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के विरुद्ध अभियान में मिलेगी सफलता- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नशामुक्त भारत के संकल्प तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह के वर्ष 2029 तक भारत को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस दिशा में जनभागीदारी के साथ निरंतर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सलवाद जैसी बड़ी लड़ाई में भी विजय प्राप्त की है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के विरुद्ध अभियान में भी सफल होगी।

छात्रवृत्ति और आवास राशि पर फूटा छात्रों का गुस्सा, जयस ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

इंदौर। इंदौर सहित प्रदेशभर में छात्रवृत्ति और आवास राशि के भुगतान में हो रही देरी को लेकर छात्रों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। शुक्रवार को जयस छात्र संगठन (JCS) ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और संबंधित छात्रवृत्ति, आवास एवं नर्सिंग विद्यार्थियों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। जिला अध्यक्ष लखन बामनिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के हजारों विद्यार्थियों की वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की छात्रवृत्ति और छात्रावास/आवास राशि अब तक अटक ही हुई है। आर्थिक सहायता नहीं मिलने से कई छात्र पढ़ाई



छोड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है। संगठन ने कहा कि छात्रवृत्ति और आवास राशि में लगातार हो रही देरी ने गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कमर तोड़ दी है।



किया, भोजन और शैक्षणिक खर्च उठाना मुश्किल हो गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या पर मौन बने हुए है। ज्ञापन में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के उन विद्यार्थियों की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई जिन्हें 'अनस्यूटेबल'

घोषित कर दिया गया है। संगठन ने मांग की कि इन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद किया जाए और उनके लिए स्थायी समाधान निकाला जाए। जयस छात्र संगठन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि संबंधित भुगतान और छात्रवृत्ति के मुद्दों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन का कहना है कि छात्रों के संवैधानिक और शैक्षणिक अधिकारों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यदि उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया गया तो यह मुद्दा जल्द ही व्यापक छात्र आंदोलन का रूप ले सकता है।

कोरबा भिलाई बाजार-विकास खंड पाली अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल आमगांव

में मानदेय शिक्षक के पद पर इन्द्रजीत सिंह कंवर निवासी खराबहार की नियुक्ति 1 जुलाई को हुई, इन्द्रजीत का पेपर सत्यापन 30 जून को चयन समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और स्कूल के प्राचार्य एल.के. डहरिया, एवं स्कूल स्टॉप की उपस्थिति में इन्द्रजीत का चयन हुआ, 1 जुलाई से इन्द्रजीत स्कूल पहुंच कक्षा 9 वीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया अचानक से स्कूल के प्राचार्य एल.के. डहरिया, ने इन्द्रजीत जब 8 जुलाई को स्कूल पहुंचा तो प्राचार्य बोले के तुम आज के बाद स्कूल मत आना तुम्हारी जगह नेहा कुरें को पदस्थ कर दिया गया है, वही इन्द्रजीत का कहना है कि जब मेरी नियुक्ति चयन समिति द्वारा की मेरा परसेंटेज बस को देख कर दिया गया है तो आप मुझे अचानक से बिना कुछ सूचना दिए कैसे हटा रहे हैं तो प्राचार्य बोले कि जिसको मन करे उसको नियुक्त कर सकता हूं।

कहकर मुझे स्कूल आने से मना कर दिए, प्राचार्य के इस बर्ताव से इन्द्रजीत मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बात कर रहा है, जब हम फोन से प्राचार्य एल.के. डहरिया से संपर्क किये तो उनका कहना है कि नेहा पूर्व में यहां पढ़ा चुकी है इसलिए उसे दोबारा नियुक्त किया गया है, जबकि नेहा का अंक इन्द्रजीत के अंक से बहुत कम है। वहीं इन्द्रजीत ने बताया कि मानदेय शिक्षक बनने के पूर्व वह निजी कंपनी में काम करता था मानदेय शिक्षक में चयन होने पर वह उस काम को छोड़ कर मानदेय शिक्षक बन बहुत खुश था लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी बस चार दिन की थी, प्राचार्य द्वारा इन्द्रजीत को हटा देने से उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब उसके हाथ से निजी कंपनी का काम था वह भी



पंकज धुवा (अध्यक्ष जनभागीदारी शिक्षा समिति)

हमारे समिति द्वारा इन्द्रजीत सिंह कंवर खराबहार का चयन किया उसके अच्छे अंक को देखकर किया गया था, उसका सभी विषयों में अच्छा अंक है, जिस दिन चयन हुआ स्कूल के प्राचार्य श्री डहरिया जी भी थे सभी की सहमति से इन्द्रजीत का हिंदी विषय के लिए मानदेय शिक्षक के रूप में चयनित हुआ, इन्द्रजीत कुछ दिन बच्चों को पढ़ाया बच्चे उसके पढ़ाई से काफी खुश थे, फिर अचानक से प्राचार्य श्री डहरिया 7 जुलाई को हमारे समिति को बिना सूचना दिए इन्द्रजीत को हटाकर नेहा कुरें को मानदेय शिक्षक के रूप में चयन कर लिए, जिसका विरोध हमारे समिति द्वारा किया गया, लेकिन श्री डहरिया जिलाशिक्षा अधिकारी का फोन में नेहा कुरें को रखने की बात कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में इन्द्रजीत ही मानदेय शिक्षक रहे, हमारी समिति इन्द्रजीत का चयन किया है न कि नेहा का।

के. गोभिल (बीईओ पाली)

हमें जानकारी मिली है कि आमगांव के स्कूल में इन्द्रजीत सिंह कंवर का चयन मानदेय शिक्षक के रूप में हुई है,

चला गया और बिना सूचना दिए प्राचार्य अपने परिचित को पुनः स्कूल में पदस्थ कर लिए। इन्द्रजीत ने प्राचार्य के खिलाफ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, व जिलाधीश को पत्र लिखकर न्याय की मांग कर रहा है।

शिशुपाल जी! शिकायत हुई तो नींद खुली, वरना स्टॉप डैम फाइलों में ही बहता रहता?"

सूर्या परमार

पहले पोर्टल पर 'कार्य प्रगति पर', अब जवाब में 'काम पूरा'... आखिर सच कौन बोल रहा है?"

शुजालपुर। ग्राम पंचायत धनाना का स्टॉप डैम अब सिर्फ निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के टकराव का मामला बनता जा रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद उपयंत्री शिशुपाल भदोरिया ने जवाब दिया कि कोई नया चेक डैम नहीं बना, बल्कि पुराने स्टॉप डैम को लगभग 49 हजार की लागत से चेक डैम में परिवर्तित कर दिया गया।

लेकिन शिशुपाल जी, एक सवाल तो बनता है...

जब शिकायत दर्ज हुई थी और मौके पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपकी तकनीकी नजर आखिर



कहां थी? क्या निरीक्षण सिर्फ शिकायत आने के बाद ही होता है? या फिर पहले कागज चलते हैं और बाद में काम? पंचायत दर्पण पर पहले "कार्य प्रगति पर" लिखा गया। अब वही विभाग कह रहा है कि काम हो चुका है।

आखिर जनता किस बात पर भरोसा करे—पोर्टल पर या प्रतिवेदन पर? यदि 49 हजार का कार्य वास्तव में हुआ है तो माप पुस्तिका (MB), कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, भुगतान विवरण और मौके के पहले व बाद के फोटो सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? आखिर सरकारी पैसे

से हुए काम को छिपाने की जरूरत किसे है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिकायत के बाद रिकॉर्ड को सही ठहराने की कोशिश हो रही है, या फिर वास्तव में समय पर कार्य हुआ था? यदि काम समय पर हुआ था, तो उस समय उसका रिकॉर्ड और प्रमाण सामने क्यों नहीं आए? अब निगाहें जनपद पंचायत और जिला प्रशासन पर हैं। क्या पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच होगी, या फिर सिर्फ एक प्रतिवेदन के सहारे फाइल बंद कर दी जाएगी?

बड़ा सवाल-

शिशुपाल जी, अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ था, तो शिकायत के बाद ही जवाब क्यों आया? और अगर काम पहले से था, तो जनता को वह मौके पर पहले क्यों नहीं दिखा? आखिर सच्चाई कागजों में है या जमीन पर?

धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना के सख्त निर्देश: जिले में लागू हुआ 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान

दिलीप पाटीदार

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धार जिले में सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर हो रही वृद्धि और उनमें होने वाली जनहानि को देखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब जिले की राजस्व सीमा के भीतर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन प्रदान नहीं किया

जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए आई.एस.आई. मार्का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और इसका पालन न करना जीवन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यह आदेश 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है और 06 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल न दें; ऐसा न करने पर संबंधित पंप संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति,

संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश के अतिरिक्त प्रभावी रहेगा, हालांकि चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों (Medical Emergency) में इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। चूंकि यह आदेश जनहित में है और सभी नागरिकों व पेट्रोल पंप संचालकों को संबोधित है, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। सभी से आग्रह है कि वे सड़क सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

मिनी ट्रक को चंद घंटों में कुठला पुलिस ने किया बरामद अज्ञात चोर की तलाश जारी

नवल किशोर

कटनी। कटनी जिले की कुठला पुलिस ने ट्रक चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी गया करीब 13 लाख रुपये मूल्य का टाटा 709 मिनी ट्रक (मोबाइल क्रैन) चंद घंटों के भीतर बरामद कर लिया। मामले में अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार, पुरैनी निवासी यश नामदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह टाटा 709 मिनी ट्रक (क्रमांक GJ05BZ9174) में हेलपर है। 8 जुलाई की

रात चालक प्रकाश साहू के साथ ट्रक को पुरैनी स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने सड़क किनारे खड़ा किया गया था, जहां से अज्ञात चोर वाहन चोरी कर ले गए। रिपोर्ट के आधार पर कुठला थाना में अपराध क्रमांक 587/26 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की।

वाहन में लगे GPS सिस्टम की मदद से ट्रक की लोकेशन ट्रेस की गई और जबलपुर जिले के ग्राम बड़खेरा बिहला मोड़ के कच्चे मार्ग से ट्रक को बरामद कर विधिवत जब्त कर लिया गया। वाहन की पहचान वाहन स्वामी एवं साक्षियों द्वारा की गई। पुलिस अब चोरी करने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखलेश दाहिया के नेतृत्व में विनोद सिंह, प्रधान आरक्षक अजीत मिश्रा, आरक्षक बुद्ध कुमार एवं राजू मार्कों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दिव्यांचल मैरिज गार्डन के सामने तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने ऑटो को मारी टक्कर 3-4 बच्चे घायल

कटनी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिव्यांचल मैरिज गार्डन के सामने स्कूली बच्चों से भरा एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा के ड्राइवर ने पीछे से ऑटो को ठोकर मारी ऑटो



पालट मौके पर चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त वहां मौजूद स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत तत्परता दिखाई। बिना वक्त गंवाए सीधे मौके पर पहुंचकर ऑटो से बच्चों को बाहर निकाला।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस

हादसे में ऑटो सवार 3 से 4 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है इस हादसे ने एक बार फिर

स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्षमता से अधिक और तेज रफ्तार दौड़ने वाले इन ई रिक्शा और स्कूली ऑटो पर लगाम कब लगेगी? घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई।

जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का महापौर श्रीमती सूरि ने किया निरीक्षण

नवल किशोर

बहुप्रतीक्षित परियोजना से शहर को मिलेगी सुगम एवं सुरक्षित यातायात की सौगात, शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश



कटनी। शहर की बहुप्रतीक्षित जगन्नाथ चौक से घंटाघर तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। गुरुवार को महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरि ने पार्षद जनप्रतिनिधियों एवं निगम अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मार्ग का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान महापौर श्रीमती सूरि ने बताया कि यह सड़क शहर के सबसे महत्वपूर्ण एवं बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों में से एक है। वर्षों से मार्ग संकरा होने के कारण यहां प्रतिदिन यातायात का भारी दबाव रहता था, जिससे नागरिकों को आवागमन में

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सड़क चौड़ीकरण पूर्ण होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगी।

वर्तमान में मार्ग पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में शीघ्र पूर्ण किए जाएं, ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर का समग्र विकास एवं नागरिकों की सुविधा नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर की

यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने महापौर श्रीमती सूरि को शेष कार्यों की प्रगति से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने सभी संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान महापौर श्रीमती सूरि ने जलपा देवी वार्ड के अन्य स्थलों का भी भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य डॉ. रमेश सोनी, सुभाष शिबू साहू, एडवोकेट सुरेंद्र गुप्ता, पार्षद शकुंतला सोनी, सहायक यंत्री सुनील सिंह, उपयंत्री रवि हनोते, मोना करेरा, मृदुल श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति रही।

वन्यजीवों का काला कारोबार बेनकाब: सीबीआई-डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई में 53 संरक्षित जीव बचाए, 6 तस्कर गिरफ्तार

देश में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की संयुक्त टीम ने एक संगठित तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

कार्रवाई के दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 53 संरक्षित वन्यजीव और पक्षियों को सुरक्षित बरामद कर बचाया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह गिरोह दुर्लभ और संरक्षित जीवों की अवैध खरीद-फरोख्त में सक्रिय था। बरामद किए गए सभी जीवों को चिकित्सकीय परीक्षण और देखभाल के बाद महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल

के वन विभागों को सौंप दिया गया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि इस तस्करी नेटवर्क की जड़ें किन राज्यों और देशों तक फैली हुई हैं। मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों और वित्तीय लेन-देन की जांच के जरिए गिरोह के अन्य सदस्यों और संभावित अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की पड़ताल की जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है

कि वन्यजीव तस्करी केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि जैव विविधता और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। दुर्लभ प्रजातियों की अवैध तस्करी से पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है और कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं। यह कार्रवाई वन्यजीव अपराधों के खिलाफ एजेंसियों की सतर्कता का महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।

निशानेबाजी में चमके बुरहानपुर के लाल: एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अहद को गोल्ड, मोनिस ने जीता ब्रॉन्ज

महेन्द्र मालवीय

रणजीत टाइम्स

इंदौर के बीएसएफ शूटिंग रेंज में आयोजित 29वीं एमपी स्टेट .22 राइफल पिस्टल चैंपियनशिप (3 से 7 जुलाई 2026) में बुरहानपुर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में मोहम्मद अब्दुल अहद कुरैशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं, जिले के ही मोनिस मुशरफ हबीब ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए तृतीय स्थान (ब्रॉन्ज मेडल) हासिल किया। खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने उन्हें सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कड़ी मेहनत और बुरहानपुर से भोपाल तक का सफर

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए निशानेबाजों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अहद और मोनिस पिछले काफी समय से इस चैंपियनशिप के लिए कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास कर रहे थे। प्रशिक्षण के लिए दोनों खिलाड़ियों ने बुरहानपुर से भोपाल

तक का सफर तय किया और कोच के मार्गदर्शन में अपनी तकनीकों को सुधारा। उनकी इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी लगन और परिवार का अटूट समर्थन रहा है।

सफलता का श्रेय अपनों को दिया मोहम्मद अब्दुल अहद कुरैशी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच काशिफ लियाकत सर, अपने नाना एम.एस. खान (रिटायर्ड कमिश्नर, भोपाल), बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस दीदी, रुद्रेश्वर इंडोले जी, पिता मोहम्मद शिफाउल्लाह हाशमी, माता डॉ. निखत अफरोज और भाई उमर आरिफ को दिया।

अहद ने कहा कि इन सभी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मोनिस मुशरफ हबीब ने बताया कि अब्दुल अहद ही उनकी प्रेरणा हैं। उन्होंने अपनी सफलता के लिए कोच मोहम्मद काशिफ लियाकत सर के कुशल मार्गदर्शन, अपने पिता मुशरफ जमील, माता अनिस जहां और बड़े भाई दानिश हबीब के सहयोग व दुआओं का आभार व्यक्त किया, जिससे उन्हें खेल में एक नई दिशा मिली। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे बुरहानपुर जिले में हर्ष का माहौल है और खेल प्रेमियों द्वारा उन्हें लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं।

निशानेबाजी में चमके बुरहानपुर के लाल: एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में अहद को गोल्ड, मोनिस ने जीता ब्रॉन्ज

महेन्द्र मालवीय

रणजीत टाइम्स

इंदौर के बीएसएफ शूटिंग रेंज में आयोजित 29वीं एमपी स्टेट .22 राइफल पिस्टल चैंपियनशिप (3 से 7 जुलाई 2026) में बुरहानपुर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में मोहम्मद अब्दुल अहद कुरैशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं, जिले के ही मोनिस मुशरफ हबीब ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए तृतीय स्थान (ब्रॉन्ज मेडल) हासिल किया। खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक सफलता पर बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने उन्हें सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कड़ी मेहनत और बुरहानपुर से भोपाल तक का सफर

इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए निशानेबाजों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया था। अहद और मोनिस पिछले काफी

समय से इस चैंपियनशिप के लिए कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास कर रहे थे। प्रशिक्षण के लिए दोनों खिलाड़ियों ने बुरहानपुर से भोपाल तक का सफर तय किया और कोच के मार्गदर्शन में अपनी तकनीकों को सुधारा। उनकी इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी लगन और परिवार का अटूट समर्थन रहा है।

सफलता का श्रेय अपनों को दिया मोहम्मद

अब्दुल अहद कुरैशी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच काशिफ लियाकत सर, अपने नाना एम.एस. खान (रिटायर्ड कमिश्नर, भोपाल), बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस दीदी,

रुद्रेश्वर इंडोले जी, पिता मोहम्मद शिफाउल्लाह हाशमी, माता डॉ. निखत अफरोज और भाई उमर आरिफ को दिया। अहद ने कहा कि इन सभी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही वे आज

इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मोनिस मुशरफ हबीब ने बताया कि अब्दुल अहद ही उनकी प्रेरणा हैं। उन्होंने अपनी सफलता के लिए कोच मोहम्मद काशिफ लियाकत सर के कुशल मार्गदर्शन, अपने पिता मुशरफ जमील, माता अनिस जहां और बड़े भाई दानिश हबीब के सहयोग व दुआओं का आभार व्यक्त किया,



जिससे उन्हें खेल में एक नई दिशा मिली। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे बुरहानपुर जिले में हर्ष का माहौल है और खेल प्रेमियों द्वारा उन्हें लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं।

विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी

नवल किशोर

न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित, भुगतान में देरी पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान

कटनी । ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) - वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू की गई है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित मनरेगा व्यवस्था का स्थान नए कानून ने ले लिया है। इस कानून का उद्देश्य वर्ष 2047 तक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, कुशल और आधुनिक बनाना है।

125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी

नए कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने देशभर में न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है, जिससे लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी।

भुगतान में देरी पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान

जीरामजी कानून में मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि के बाद भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकारों को बुवाई एवं कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसम में अधिकतम 60 दिनों तक रोजगार कार्य स्थगित करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है। वहीं पात्र व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है।

चार विषयगत स्तंभ पर आधारित योजना

जी राम जी योजना चार प्रमुख विषयगत स्तंभों पर आधारित है, जो गांव के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसके तहत कुल 318 कार्यों को शामिल किया गया है। जिनमें जल सुरक्षा के 107, ग्रामीण अवसंरचना के 90, आर्थिक संपत्ति से जुड़े 86 एवं आपदा न्यूनीकरण से जुड़े 35 कार्य हैं, जो सुरक्षित, समृद्ध और सतत ग्राम विकास की नींव मजबूत करेंगे।

सांदीपनि स्कूल बना अव्यवस्थाओं का अखाड़ा, सपनों की पाठशाला में लापरवाही का पाठ

करोड़ों की लागत से बने उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, कई कक्षाएं शिक्षक विहीन, लैब पर ताले और हर तरफ गंदगी

महेन्द्र मालवीय रणजीत टाइम्स

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी सांदीपनि विद्यालय योजना का उद्देश्य सरकारी बच्चों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देना है। लेकिन बुरहानपुर जिले के शाहपुर स्थित सांदीपनि विद्यालय की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहां मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, कई कक्षाओं में शिक्षक नहीं हैं, लैब पर ताले लटके हैं, परिसर में गंदगी पसरी है और जिम्मेदार अधिकारी नदारद मिले। हमारी टीम की यह विशेष पड़ताल देखिए... यह है शाहपुर का सांदीपनि विद्यालय... जहां करीब 1300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां 22 नियमित और 13 अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से अब भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। करोड़ों की लागत से तैयार इस मॉडल स्कूल में व्यवस्थाएं आदर्श होने की बजाय बदहाल नजर आईं, जैसे ही हमारी टीम स्कूल परिसर में पहुंची, सबसे पहले जो तस्वीर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। कक्षा तीसरी के मासूम छात्र हाथों में झाड़ू लेकर स्कूल की सफाई करते मिले। बच्चों से परिसर और मैदान का कचरा भी उठवाया जा रहा था।

आखिर सवाल यह है कि क्या इन बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा गया है... या सफाई करने के लिए? जब इस संबंध में शिक्षिका आशा वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चपरासी नहीं आया था, इसलिए बच्चों से झाड़ू लगवाई गई। जबकि विद्यालय



में सफाई के लिए चार चपरासी पदस्थ हैं। ऐसे में बच्चों से सफाई करवाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। स्कूल परिसर में आगे बढ़ने पर गंदगी की एक और तस्वीर सामने आई। मैदान और बरामदों में जगह-जगह गुटखा और पान मसाले के रैपर पड़े मिले। सवाल यह भी उठता है कि आखिर यह गुटखा पाउच स्कूल परिसर में आए कैसे? क्या इनका उपयोग छात्र करते हैं या फिर कोई और? जब हमारी टीम कक्षा पांचवीं में पहुंची तो दोनों सेक्शन शिक्षक विहीन मिले। बच्चे अकेले बैठे थे। कुछ देर बाद शिक्षक पहुंचे और उन्होंने बताया कि वे ई-अटेंडेंस लगाने गए थे। लेकिन सवाल यह है कि सुबह साढ़े दस बजे शुरू होने वाले विद्यालय में 11 बजकर 15 मिनट तक उपस्थिति दर्ज करना आखिर किस व्यवस्था का हिस्सा है? इतना ही नहीं, बच्चों की कक्षा में कबाड़ तक रखा हुआ मिला।

पड़ताल आगे बढ़ी तो अव्यवस्थाओं की परतें खुलती चली गईं। बरामदों में धूल, कमरों में गंदगी, STEM लैब धूल से अटी हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष पर ताला और आईसीटी लैब भी बंद मिली। जिन कंप्यूटरों से बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिलनी थी, वे धूल फांकते नजर आए। फिजिक्स लैब के उपकरण भी उपयोग के इंतजार में पड़े मिले, कक्षा 11वीं कॉमर्स में भी विद्यार्थियों को शिक्षक का इंतजार था। अंग्रेजी का पीरियड होना था, लेकिन अतिथि शिक्षक का कार्यभार ही नहीं मिला था। नतीजा... बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

कक्षा आठवीं में एक और तस्वीर सामने आई। शिक्षक नरेंद्र विद्यार्थियों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल फोन पर व्यस्त मिले। पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे फोन पर बात कर रहे थे, जबकि विद्यालय में कक्षा के दौरान मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित माना जाता है। जब हमारी टीम प्राचार्य कक्ष पहुंची तो वहां भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। कार्यालय में पंखे और लाइटें बेवजह चल रही थीं। कैमरा देखते ही कर्मचारियों ने स्विच बंद किए, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ।

सवाल केवल एक स्कूल का नहीं... बल्कि उस भरोसे का है, जिसके साथ गरीब और ग्रामीण परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए सांदीपनि विद्यालय भेजते हैं। जब बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू हो... जब स्मार्ट लैब पर ताले लटके हों... जब कक्षाएं शिक्षक विहीन हों... जब परिसर गुटखे के रैपर और धूल से भरा हो... और जब जिम्मेदार अधिकारी ही अनुपस्थित मिलें... तो फिर करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आखिर कैसे पूरा होगा? पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार केवल जांच और लिखित कार्रवाई की बात करती रहीं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही पर स्पष्ट जवाब देने से बचती नजर आईं।

अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इन लापरवाहियों पर क्या कार्रवाई करता है... और क्या शाहपुर का सांदीपनि विद्यालय वास्तव में बच्चों के सपनों की पाठशाला बन पाएगा... या फिर अव्यवस्थाओं का अखाड़ा बना रहेगा।

सब इंस्पेक्टर भर्ती में सनराइज फिजिकल अकादमी का जलवा

ग्वालियर संभाग से सर्वाधिक 9 अभ्यर्थियों का चयन, कई ने प्रदेश की मेरिट में बनाई जगह

दिव्यानंद अर्गल



लगातार उत्कृष्ट परिणाम दे रही है। अकादमी के संचालक मंडल ने इस सफलता का श्रेय अनुभवी प्रशिक्षकों कोच पीएम सर एवं अजीत सर के कुशल मार्गदर्शन, व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली और विद्यार्थियों की कठिन मेहनत को दिया है। प्रशिक्षकों ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में आदित्य सिंह सिकरवार ने सामान्य वर्ग में मध्यप्रदेश में 20वीं रैंक, मोनू सिंह

तोमर ने सामान्य/सैनिक श्रेणी में प्रदेश में प्रथम रैंक, अक्षय मोर्य ने अनुसूचित जाति वर्ग में 9वीं रैंक, अभिषेक मोर्य ने अनुसूचित जाति वर्ग में 13वीं रैंक, अंकित कुमार माणवी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग में 38वीं रैंक, खुशबू तोमर ने सामान्य वर्ग में प्रदेश में 9वीं रैंक, शिवांगी ने मध्यप्रदेश पुलिस मेरिट में 9वीं रैंक, प्रिन्सी कुशवाह ने ओबीसी वर्ग में 99वीं रैंक प्राप्त की, जबकि राजा यादव का भी सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ है। अकादमी प्रबंधन ने चयनित सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता आने वाले प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। संस्थान का लक्ष्य भविष्य में और अधिक युवाओं को पुलिस, सेना एवं अन्य सुरक्षा सेवाओं में चयनित कर प्रदेश का नाम रोशन करना है।

बॉक्स : चयनित अभ्यर्थी- (बॉक्स बनाकर

लगा देना)

आदित्य सिंह सिकरवार - सामान्य वर्ग, मध्यप्रदेश 20वीं रैंक

मोनू सिंह तोमर- सामान्य/सैनिक श्रेणी, मध्यप्रदेश प्रथम रैंक

अक्षय मोर्य-अनुसूचित जाति, मध्यप्रदेश 9वीं रैंक

अभिषेक मोर्य-अनुसूचित जाति, मध्यप्रदेश 13वीं रैंक

अंकित कुमार माणवी-अनुसूचित जनजाति, मध्यप्रदेश 38वीं रैंक

खुशबू तोमर-सामान्य वर्ग, मध्यप्रदेश 9वीं रैंक

शिवांगी-मध्यप्रदेश पुलिस मेरिट 9वीं रैंक

प्रिन्सी कुशवाह-ओबीसी वर्ग, मध्यप्रदेश 99वीं रैंक

राजा यादव

कटनी 5 करोड़ की 'माइनिंग', धोखाधड़ी ब्लैकमेलिंग का पर्दाफाश माधव नगर थाने में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नवल किशोर

कटनी। माधवनगर थाना क्षेत्र से माइनिंग और खनिजों के कारोबार में धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और खुली रंगदारी का एक ऐसा सनसनीखेज महाघोटाला सामने आया है, जिसने पूरे महाकौशल के माइनिंग सिंडिकेट के खौफनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया है। 'क्वांटम मिनरल्स' फर्म के साथ करीब 4 से 5 करोड़ रुपये की जालसाजी और धोखाधड़ी के इस संगठित खेल में मुख्य सरगना आदिल अहमद और ओमप्रकाश पाठक समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इस पूरे गिरोह ने न सिर्फ करोड़ों रुपये की जबरन वसूली की, बल्कि जब पीड़ित ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर खदान पर ही ताला लगवा दिया। सबसे धिनौना और शातिर पहलू तब सामने आया जब आरोपियों की ब्लैकमेलिंग और रंगदारी की स्क्रिप्ट फेल हो गई। 'इस्मार्ट एण्ड सन्स' के आदिल अहमद और उसके गुर्गों ने टिकरिया मुड़वारा स्थित 12.679 हेक्टेयर की लेटेराईट एवं बॉक्साइट खदान को शुरू कराने, एनओसी (NOC) दिलाने और आईबीएम (IBM) की कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर क्वांटम मिनरल्स से कई किश्तों में



करोड़ों रुपये ऐंटे।

लेकिन जैसे ही साल 2025 में खदान सुचारू रूप से चालू हुई, इस सिंडिकेट की नीयत डोल गई। आरोपियों ने पहले नागपुर और फिर कटनी के बंद कमरों में पीड़ित फर्म के मालिक को बुलाकर 75 लाख रुपये की अतिरिक्त रंगदारी मांगी और धमकी दी कि "पैसा नहीं मिला तो खदान किसी और को बेच देंगे।" जब क्वांटम मिनरल्स ने इस नाजायज और अवैध वसूली के आगे झुकने से साफ मना कर दिया, तब

इस सिंडिकेट ने अपनी चाल बदली। आरोपियों ने सीधे सरकारी सिस्टम को ही हथियार बना लिया:

खनिज विभाग में फर्जीवाड़ा: आरोपियों ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत खनिज शाखा कटनी में आवेदन के साथ खुद का झूठा शपथ पत्र पेश कर दिया। जिस खदान को चालू कराने और पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए इन्होंने करोड़ों लिए थे, उसी खदान के खिलाफ झूठे तथ्यों का जाल बुनकर खनिज

कार्यालय को गुमराह किया।

करोड़ों का नुकसान: इस झूठे हलफनामे के दम पर माइनिंग विभाग से खदान का काम रुकवा दिया गया, जिससे क्वांटम मिनरल्स को सीधे तौर पर 4 से 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम आर्थिक चपत लगी। मकसद साफ था—खदान बंद होगी, तो पीड़ित आर्थिक रूप से टूटेगा और अंततः 75 लाख की फिरीती देने पर मजबूर हो जाएगा। एफआईआर के पन्नों से साफ है कि यह महज कोई कागजी हेराफेरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह 'अंडरवर्ल्ड स्टाइल' में वसूली का संगठित ताना-बाना था। आरोपियों ने पीड़ित को दबाव में लेने के लिए बकायदा नागपुर में एक गुप्त मीटिंग रखी, जहां सीधे टेबल पर धमकी परोसी गई। इसके बाद कटनी की बैठकों में भी लगातार मानसिक और आर्थिक टॉर्चर किया गया। इसी बीच शातिर आदिल अहमद ने इस खदान का सौदा गुपचुप तरीके से 'विक्ट्री मिनरल्स' के मालिकों के साथ भी कर के पैसे बटोर लिए। यानी एक ही प्रॉपर्टी को अलग-अलग मोहरों को दिखाकर करोड़ों रुपये अंदर करने का यह बड़ा नेक्सस था।

माधवनगर थाना पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह सनसनीखेज मामला टिकरिया मुड़वारा में स्थित 12.679 हेक्टेयर की लेटेराईट और बॉक्साइट खदान को पुनः शुरू कराने के नाम पर की गई बड़ी धोखाधड़ी का है। क्वांटम मिनरल्स फर्म के प्रबंधक

संजीव बोहरे की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0624/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और 318(4) (जालसाजी व ठगी) के तहत कायमी की गई है। मामले में आदिल अहमद, हुज्जू, ओम प्रकाश पाठक, नानू मिश्रा, अमन मिश्रा, अलाउद्दीन, सरफराज अहमद, शबनम अहमद और तनवीर खान सहित कुल 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक संतोष सिंह इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए गहन विवेचना कर रहे हैं। पुलिस अब सिंडिकेट के बैंक खातों और खनिज विभाग में पेश किए गए संदिग्ध दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है।

शिकायतकर्ता संजीव बोहरे की ठोस शिकायत के बाद हरकत में आई माधवनगर थाना पुलिस ने सभी 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अब सिंडिकेट के उन तमाम बैंक खातों को खंगाल रही है जिनमें 'लेयरिंग' के जरिए लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही, खनिज कार्यालय से उस झूठे शपथ पत्र और आवेदन को भी जब्त किया जा रहा है, जिसके जरिए सरकारी विभाग को गुमराह कर खदान बंद करवाई गई थी।

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने किया नगर का औचक निरीक्षण, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश

धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन भ्रमण कर विकास कार्यों और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शासकीय भूमि के सदुपयोग और निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

शासकीय भूमि का भविष्योन्मुखी उपयोग हो

भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने नवीन लालबाग के सामने रिक्त शासकीय भूमि का अवलोकन किया। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि इस भूमि पर 'कंजर्वेशन' निर्माण हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल निर्माण करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रोजेक्ट से भविष्य में जनता को अधिकतम लाभ मिले। साथ ही, शहर में स्थित जर्जर और खण्डर हो चुके शासकीय भवनों को चिन्हित कर उनके स्थान पर नए निर्माण प्लान तैयार करने को कहा ताकि सरकारी संपत्ति का उचित उपयोग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया



कि किसी भी शासकीय कार्य को लंबित न रखा जाए और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्तावों की आवश्यकता है, उन्हें अविलंब प्रस्तुत करें। इसके अलावा, 'लो-कोस्ट' प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

स्वच्छता और आवास योजनाओं पर जोर

किला मैदान के सामने रिक्त भूमि का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने वहां प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किला मैदान के पास गंदगी देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी

जताई और नगर पालिका अधिकारियों को डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली को प्रभावी बनाने और पूरे शहर में स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

एसपीडीए मैदान का समयबद्ध विकास

एसपीडीए मैदान के निरीक्षण के दौरान उन्होंने खेल अधिकारी, सीएमओ और तहसीलदार को निर्देशित किया कि मैदान के बाहर बन रहे शौचालयों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मैदान के चारों ओर आवागमन के लिए सुगम रास्ते सुनिश्चित करने और चल रहे सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आम नागरिक जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। कलेक्टर के इस दौरे से प्रशासनिक तंत्र में सक्रियता बढ़ी है और उम्मीद है कि शहर के विकास कार्यों में अब और अधिक तेजी आएगी। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अंकिता प्रजापति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री कुंवर विश्वनाथसिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

डबल डेकर ब्रिज की लोड टेस्टिंग सफल

इंदौर। प्राधिकरण द्वारा लवकुश चौराहा पर बनवाए गए 175 करोड़ रुपये के डबल डेकर ब्रिज की 48 घंटे की लोड टेस्टिंग सफल हुई। हालांकि उसका अभी परीक्षण जारी है और विधिवत रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संभव है जल्द ही एक लेन पर यातायात शुरू भी कर दिया जाए। दूसरी तरफ ब्रिज के नीचे की गड्ढामय हो चुकी सर्विस रोड को भी 13 करोड़ रुपये खर्च कर सीमेंटीकरण किया जा रहा है। यातायात रोककर यह सड़क निर्माण चल रहा है। हालांकि अभी गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी भी उठाना पड़ रही है। प्राधिकरण की मंशा है कि अगले दो-तीन महीनों में डबल डेकर ब्रिज पर से यातायात शुरू कर दिया जाए। वैसे भी यह प्रोजेक्ट गत वर्ष अंत तक शुरू हो जाना था। अभी 25-25 टन के 16 डम्पर्स को खड़ा करवाकर 400 टन का वजन इस ब्रिज पर डाला गया और अलग-अलग पैरामीटर के आधार पर जांच-पड़ताल की गई। हालांकि प्रथमदृष्ट्या किया गया लोड टेस्ट सफल रहा, मगर अभी विधिवत रिपोर्ट हर तरह की ली गई रीडिंग के आधार पर तैयार की जा रही है। वहीं ब्रिज के नीचे 13 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर प्राधिकरण सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनवा रहा है, क्योंकि यह सर्विस रोड भी अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरी तरफ प्राधिकरण ने अपनी योजनाओं में शामिल जमीनों के नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की है, क्योंकि नामांतरण ना होने से कई बार जमीनें बिक जाती है या अन्य तरह की धोखाधड़ी संभव है।

संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में सरदार सरोवर परियोजना में आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री को लेकर बैठक आयोजित

विस्थापितों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश

राजेश धाकड़

इंदौर, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में सरदार सरोवर परियोजना में विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री एवं अन्य विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री कार्यों में तेजी लायी जाये।

शिकायत निवारण प्राधिकरण की एकल पीठ एवं युगल पीठ में लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने आगे कहा कि सरदार सरोवर परियोजना में धार, बड़वानी, खरगोन और आलीराजपुर जिले के प्रभावित



हुए विस्थापितों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। जिसमें सड़क, पानी, बिजली, पंचायत भवन, आँगनवाड़ी, शुद्ध जल आदि शामिल हैं। संभागायुक्त ने कहा कि अधिकारी पुनर्वास स्थलों पर जायें और वहां चल रहे कार्यों की देखें और उसकी सतत मॉनीटरिंग करें।

बैठक में सूचना के अधिकार के तहत लंबित प्रकरणों की स्थिति,

भूखण्ड पंजीयन, पुनर्वास, सर्विस प्रोवाइडर आदि विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में एनवीडीए के अपर संचालक श्रीमती सपना अनुराग जैन, शिकायत निवारण प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सारिका भूरिया, संयुक्त संचालक श्री रजनीश कसेरा सहित विभिन्न विभागों के सहायक संचालक एवं संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

दिल्ली हाईकोर्ट से चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका, एनएसई को-लोकेशन मामले में याचिका खारिज; अदालत ने दखल देने से किया इनकार



नई दिल्ली। राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के चर्चित को-लोकेशन मामले में पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चित्रा रामकृष्ण ने जांच और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और जांच एजेंसियां कानून के

अनुसार अपनी प्रक्रिया जारी रख सकती हैं। एनएसई को-लोकेशन मामला देश के सबसे चर्चित वित्तीय मामलों में से एक है। आरोप है कि कुछ चुनिंदा ब्रोकरों को को-लोकेशन सुविधा के माध्यम से अन्य निवेशकों की तुलना में तेज पहुंच उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें अनुचित कारोबारी लाभ मिला। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। अदालत के इस फैसले के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

मेट्रो के सहारे बदलेगा इंदौर का नक्शा? कंट्रोल एरिया घोषित, अब ऊंची इमारतों और नए विकास का रास्ता



इंदौर मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्तावित 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो रिंग कॉरिडोर के दोनों ओर 500-500 मीटर क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य मेट्रो मार्ग के आसपास सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना और भविष्य में अधिक यात्रियों को मेट्रो से जोड़ना है।

प्रस्ताव के अनुसार, कंट्रोल एरिया में भवन निर्माण के नियमों में बदलाव कर अधिक ऊंचाई वाली इमारतों और मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यावसायिक) परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे मेट्रो स्टेशन के आसपास आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जिससे मेट्रो की यात्री संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञ इसे

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की अवधारणा से जोड़कर देखते हैं, जिसमें सार्वजनिक परिवहन के आसपास घनी और योजनाबद्ध बसाहट विकसित की जाती है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और शहरी यातायात को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। हालांकि, इस योजना के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। यदि सड़क, सीवर, पेयजल, पार्किंग, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं का समानांतर विस्तार नहीं किया गया, तो बढ़ता निर्माण भविष्य में यातायात और नागरिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और स्थानीय विकास एजेंसियां इस योजना को किस तरह लागू करती हैं, ताकि मेट्रो के साथ इंदौर का विकास भी संतुलित, टिकाऊ और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बन सके।

दस्तावेजों की बाधा दूर, शिक्षा का खुला रास्ता: कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने देवनगरी बस्ती के बच्चों का कराया स्कूल प्रवेश

जन्म प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और आधार कार्ड बनने से 40 से अधिक बच्चों के भविष्य को मिली नई दिशा

राजेश धाकड़ इंदौर एयरपोर्ट रोड स्थित देवनगरी बस्ती के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को भावनात्मक और प्रेरणादायी माहौल देखने को मिला। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा बच्चों के बीच पहुंचे और जमीन पर बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कुछ समय पूर्व देवनगरी बस्ती के बच्चे अपने अभिभावकों एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहित सिंह चौहान के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्टर श्री वर्मा को बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनके समग्र आईडी, आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी नहीं बन पा रहे हैं। दस्तावेजों के अभाव में बच्चों का स्कूल में प्रवेश भी प्रभावित हो रहा था। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासन एवं नगर निगम की संयुक्त टीम को आवश्यक कार्रवाई



के निर्देश दिए। इसके बाद देवनगरी बस्ती में विशेष अभियान चलाया गया। शासकीय प्राथमिक विद्यालय में दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित कर उन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनका जन्म घर पर होने के कारण नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाया था। जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद बच्चों के समग्र आईडी, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार किए गए। इस पहल से 40 से अधिक बच्चों के शिक्षा और भविष्य का रास्ता आसान हो गया।

शुक्रवार को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा स्वयं विद्यालय पहुंचे और इन बच्चों का विधिवत स्कूल प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा केवल दस्तावेजों के अभाव

में बाधित नहीं होने दी जाएगी। यदि इस प्रकार के अन्य मामले भी सामने आते हैं तो प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक दस्तावेज तैयार कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री वर्मा ने विद्यालय का निरीक्षण किया, बच्चों के साथ कक्षाओं का भ्रमण किया तथा उन्हें खेल सामग्री वितरित की। उन्होंने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बस्ती के बच्चे, अभिभावक, स्थानीय नागरिक तथा प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

इंग्लैंड से पहली बार टी20 सीरीज हारा भारत

7 साल बाद लगातार दो सीरीज हारे विश्व विजेता

नई दिल्ली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार मैच हार रही है। इंग्लैंड ने शुक्रवार (10 जुलाई) को चौथे टी20 में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने पहली बार दो या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में भारत को हराया है।

भारत ने पिछले छह में से पांच सीरीज जीते हैं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। मार्च में लगातार दूसरा विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से पहले आयरलैंड से 2 मैचों की टी20 सीरीज हारी। इससे पहले भारतीय टीम फरवरी 2019 में लगातार 2 टी20 सीरीज हारी थी। न्यूजीलैंड ने उसे 1-2 और ऑस्ट्रेलिया ने उसे 2-0 से हराया था। मौजूदा सीजन से



पहले भारत ने अपनी पिछली 12 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में से 11 में जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।

इंग्लैंड ने नौ विकेट से हराया

3-0 से बनाई अजेय बढ़त

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में हुआ। इंग्लैंड ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत को 9 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर



पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर मुकाबला जीत लिया। फिल साल्ट ने 59 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 79 रन बनाकर शानदार अर्धशतक जड़े। इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली है और 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है।

इंग्लैंड से 2018 के बाद सीरीज हारी भारतीय टीम

भारतीय टीम 2018 में इंग्लैंड दौरे पर 2 सीरीज हारी थी। वनडे में 2-1 और टेस्ट में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच खेले गई किसी भी प्रारूप की सीरीज भारतीय टीम नहीं हारी थी। वह 10 में से 8 सीरीज जीती थी। इंग्लैंड में खेले गई पिछली 2 टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रहीं।

इंग्लैंड की दूसरी बड़ी जीत- भारत ने चौथे टी20 में 37 गेंद रहते 9 विकेट से जीत हासिल की। 150 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए यह इंग्लैंड की विकेट के हिसाब से संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले उसने 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में 192 रनों के लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल किया था।

वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड में अब तक का प्रदर्शन

नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज खास नहीं रहा है। इंग्लैंड में खेले पहली तीन पारियों में लगातार वह फेल ही साबित हुए हैं। उन्होंने पहली तीन पारियों में 14, 13 और 15 रन ही बनाए हैं। अभी तक लगातार उनकी आईपीएल वाली कमजोरी ही इंग्लैंड में उजागर हुई है। वह तीनों मुकाबलों में शॉर्ट बॉल के सामने दिक्कत में दिखे हैं। पिछली दोनों पारियों में वह शॉर्ट पिच डिलीवरी पर ही आउट हुए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड सीरीज में अभी तक तीन पारियों में 42 रन ही बनाए हैं। उन्होंने 27 गेंद का सामना किया है जिसमें 5 छक्के और सिर्फ एक चौका उनके बल्ले से निकला है। मगर उनकी सबसे बड़ी दिक्कत शॉर्ट बॉल की समस्या नहीं दूर हो रही है। जोफ्रा आर्चर ने लगातार दूसरी बार वैभव का विकेट झटका है।

उन्होंने ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल में 10 गेंद पर 15 रन ही बनाए हैं। इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए मैनचेस्टर में उन्होंने 12 गेंद पर 14 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी में नॉटिंगहम में वह 13 रन ही बना पाए थे। नॉटिंगहम के बाद ब्रिस्टल में भी वह आर्चर का

5 छक्के, 27 गेंद, 42 रन



शिकार बने हैं। आर्चर के खिलाफ वैभव ने 3 पारियों में 13 गेंद पर सिर्फ 18 रन ही बनाए हैं और दो बार उनका शिकार भी वह बने हैं।

वैभव सूर्यवंशी की जगह पर मंडराया खतरा?

भारतीय टीम ने तीन महीने पहले विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन को बाहर करते हुए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह दी थी। अब वैभव ने पहली तीनों पारियों में निराश किया है। उनके अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं।

वैभव को जितनी तेजी से टीम में लाने की मांग उठ रही थी। उतनी तेजी से ही अब उनकी खामियां सामने आ रही हैं। इसी कारण सीरीज के आखिरी मुकाबले में अब उनकी जगह पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने पहली तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बनाए हैं। उनका इंटरनेशनल डेब्यू खास नहीं रहा है। अब आखिरी टी20 में उनकी जगह संजू सैमसन की एंट्री होती है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

ड्रग्स मामले में हिरासत पर सियासत: नाना पटवारी बोले- तीन साल पहले तक नशा करता था, अब पूरी तरह छोड़ चुका हूं

● कांग्रेस अध्यक्ष का भाई होना ही मेरी गलती, इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया था

इंदौर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को ड्रग्स मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना पटवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटवारी ने स्वीकार किया कि वे करीब तीन वर्ष पहले तक ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में उपचार के बाद उन्होंने नशा पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं जीतू पटवारी का भाई हूं।' उन्होंने दावा किया कि उनका किसी ड्रग तस्करी या अवैध कारोबार से कोई संबंध नहीं है। नाना पटवारी ने बताया कि वे

अपनी कार की सर्विसिंग कराने गए थे, तभी पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए साथ ले गई। उनका आरोप है कि थाने में उन्हें हिरासत में लेने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और पूरे दिन विभिन्न स्थानों पर ले जाकर पूछताछ की गई। देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी कार जिस सर्विस सेंटर पर जाती है, उसका संचालन संजय कौशल उर्फ रॉनी करता है और वहीं इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी भी काम करता है। पुलिस ने उनसे इन्हीं दोनों व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की। नाना ने स्पष्ट किया कि जिस स्कॉर्पियो वाहन की चर्चा की जा रही है, वह उनकी नहीं बल्कि संजय



कौशल की है और उसमें मिले किसी भी सामान से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विपक्षी नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके भाई का ड्रग्स तस्करी से कोई संबंध नहीं है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। दरअसल, गुरुवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने रेतमंडी चौराहे के पास से इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल उर्फ रॉनी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, दोनों के कब्जे से करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने नाना

पटवारी और मानव गंगवानी का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

जांच में जिस व्यक्ति की भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नाना पटवारी के खिलाफ पूर्व में विभिन्न मामलों में प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में पुलिस जांच जारी है और अब तक उनके खिलाफ किसी नई आपराधिक सलिस्ता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

'पेड़ लगाओ, पानी बचाओ' अभियान को अंतिम रूप, बीएसएफ परिसर में लगेंगे एक लाख पौधे, मंत्री विजयवर्गीय ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा



इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को हरियाली में भी नंबर-1 बनाने के संकल्प के साथ 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान 3.0 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। रविवार को आयोजित होने वाले 'पेड़ लगाओ, पानी बचाओ' अभियान से पहले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हातोद रोड स्थित बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के बुढ़ानिया परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंदौर में पूर्व के दोनों चरणों में रिकॉर्ड वृक्षारोपण किया

गया। पहले वर्ष 51 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिनमें रेवती रेंज में 12,40,017 पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। दूसरे चरण में करीब साढ़े 15 लाख पौधे लगाए गए। अब तीसरे चरण में 21 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में भूमि की कमी को देखते हुए इस बार वन विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का चयन किया गया है। बीएसएफ ने अपनी पथरीली एवं बंजर भूमि उपलब्ध कराई है, जहां एक लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा देवगुड़ाडिया के पीछे दतूदा टेकरी पर करीब डेढ़ लाख, सिरपुर तालाब के पीछे एक लाख तथा राऊ

तालाब की बाउंड्री पर 10 हजार पौधे रोपे जाएंगे। अभियान में आम नागरिकों के साथ बीएसएफ के जवान भी भागीदारी करेंगे। पौधों के बेहतर संरक्षण और जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए इस बार 6 से 10 फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक की पदयात्रा की सराहना करते हुए कहा कि 80 वर्ष की आयु में उनका पैदल चलना प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि कार और हवाई जहाज में घूमने तथा साइकिल पर रील बनाने वाले युवा नेताओं को उनसे सीख लेकर जमीन से जुड़कर राजनीति करनी चाहिए। हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से जुड़े सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान 'पेड़ लगाओ, पानी बचाओ' अभियान को सफल बनाने पर है।

डबल डेकर ब्रिज की लोड टेस्टिंग सफल, जल्द खुल सकता है यातायात

13 करोड़ से बन रही सीमेंट कंक्रीट सर्विस रोड, ग 1 से मिलेगी राहत



इंदौर। लवकुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा निर्मित 175 करोड़ रुपये के डबल डेकर ब्रिज की 48 घंटे तक चली लोड टेस्टिंग सफल रही है। हालांकि अभी अंतिम तकनीकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जिसके बाद ब्रिज को यातायात के लिए खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षण संतोषजनक रहने पर उन्होंने टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान 'पेड़ लगाओ, पानी बचाओ' अभियान को सफल बनाने पर है।

400 टन भार डाला गया। इस दौरान विभिन्न तकनीकी मानकों के आधार पर ब्रिज की मजबूती, झुकाव और कंपन सहित अन्य पहलुओं की जांच की गई। प्राप्त रीडिंग के विश्लेषण के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दूसरी ओर, ब्रिज के नीचे की करीब 900 मीटर लंबी सर्विस रोड का भी कायाकल्प किया जा रहा है। लंबे समय से गड़बड़ और खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट कंक्रीट

सड़क निर्माण का कार्य शुरू कराया है। निर्माण कार्य के चलते फिलहाल यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन सड़क तैयार होने के बाद क्षेत्र के हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

आईडीए का लक्ष्य अगले दो से तीन महीनों में पूरे प्रोजेक्ट को यातायात के लिए तैयार करना है। यह प्रोजेक्ट पिछले वर्ष के अंत तक शुरू होना था, लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई। अब लोड टेस्टिंग सफल होने और सर्विस रोड निर्माण शुरू होने से परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।

बालसुलभ अबोध आनंद में रहना ही सहजयोग है

मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियाँ प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शाश्वत आनंद का अनुभव करना है जो मन को पूर्ण शांति, संतुलन और संतुष्टि प्रदान करता है। सहजयोग में यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर विद्यमान मासूमियत, निर्मलता और अबोधिता के जागरण से स्वतः प्रकट होता है। अबोधिता वह दिव्य गुण है जो मनुष्य को अहंकार, छल,

कपट और कृत्रिमता से मुक्त कर सहज, सरल और प्रेमपूर्ण बनाता है। यदि अबोधिता को समझना हो तो हमें एक छोटे बालक की ओर देखना चाहिए, जो संसार की जटिलताओं और मायावी आकर्षणों से अछूता रहकर सहज हँसी, निष्कपट प्रेम और स्वाभाविक आनंद में जीता है। सहजयोग में श्री गणेश इस पवित्र अबोधिता के अधिष्ठाता माने जाते हैं और साधक के भीतर इसी दिव्य गुण की रक्षा एवं पोषण करते हैं। जब यह



मासूमियत जागृत होती है, तब व्यक्ति वर्तमान क्षण में स्थापित होकर भय, तनाव और मानसिक अशांति से मुक्त हो जाता है तथा उसका जीवन सहज आनंद

से भर उठता है। सहजयोग की संस्थापिका परम पूज्य आदिशक्ति श्री माताजी निर्मला देवी ने 22 अगस्त 1982 के अपने उद्घोषण में कहा था कि मासूमियत ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य स्वयं भी आनंद का अनुभव करता है और दूसरों के जीवन में भी आनंद का संचार करता है।

उनके अनुसार वास्तविक आनंद किसी बनावट, तर्क या प्रदर्शन का विषय नहीं, बल्कि फूल की सुगंध की तरह

स्वाभाविक रूप से खिलने वाली अवस्था है, जो किसी को चोट नहीं पहुँचाती, किसी को परेशान नहीं करती, बल्कि प्रेम, करुणा और सहजता का प्रसार करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एक निर्दोष और अबोध व्यक्ति ही उस सूक्ष्म आनंद का अनुभव कर सकता है जिसे अत्यधिक गंभीर या केवल तर्कप्रधान व्यक्ति प्रायः अनुभव नहीं कर पाता। यही कारण है कि सहजयोग का मूल उद्देश्य साधक को आत्मसाक्षात्कार के

माध्यम से इस चिरस्थायी आनंद की अवस्था तक पहुँचाना है, जहाँ जीवन सहज, संतुलित, भयमुक्त और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन जाता है। इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने के इच्छुक साधक अपने निकटतम सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.sahajayoga.org.in पर उपलब्ध विवरण देख सकते हैं। सहजयोग सदैव व पूर्णतया निशुल्क है।